ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 4, Issue 11 , November 2014 Impact Factor3.849 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

वैश्वीकरण एवं भारतीय कृषि पर इसका प्रभाव: एक महत्वपूर्ण अध्ययन

चेतना शर्मा[1], डॉ एच. पी. सिंह[2]

अर्थशास्त्र विभाग

[1,2]चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सार

आज वैश्वीकरण शब्द विश्वव्यापी विकास प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। दुनिया के प्रत्येक कोने में आवश्यक वस्तुओं को खरीदने या बेचने के कारण ही यह अब संभव है । संचार के साधन, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और परिवहन इसी की सुविधाओं का अंश है। इस प्रकार, वैश्वीकरण की अवधारणा शविकासश भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। शब्द अर्थव्यवस्था के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था एकीकरण को एकीकृत करना वैश्वीकरण का मतलब है । माल और सेवाओं, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विश्व बाजार के साथ घरेलू बाजार श्रम आदि। ग्लोलाइजेशन के माध्यम से पूंजी प्रवाह और वित्त प्रवाह की ही एक प्रक्रिया है । दूसरे देश में देश वैश्वीकरण नए शब्द है जो इस पर हावी हो गया है ।

1. प्रस्तावना

पिछली शताब्दी के नब्बे के दशक के बाद से दुनिया को केवल "वैश्वीकरण" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।देशी राज्यों की राजनीतिक सीमाओं में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार वैश्वीकरण है। व्यापक रूप से भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ है वित्त, इनपुट, आउटपुट, सूचना और विज्ञान के आंदोलन को बढ़ाना कि भौगोलिक क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रत्यक्ष रूप से खोलना निवेश और भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों में प्रवेश प्रदान करते हैं वैश्वीकरण का मतलब है एक स्थानीय स्तर से दुनिया भर में बाजार की व्याख्या। भूमंडलीकरण का एकीकरण करना है वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था और विकास की क्षमता का इष्टतम उपयोग वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विश्व कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को क्रांति ला दी है दक्षता उत्पादकता और लागत प्रतिस्पर्धा में सुधार नए वैश्वीकरण में लाया गया है विकासशील देशों के लिए अवसर विकसित देशों के बाजारों में और अधिक पहुंच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ने वादा किया कि बेहतर उत्पादकता और उच्चतर रहने वाला मानक उदारीकरण के बाद, भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा के

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 4, Issue 11 , November 2014 Impact Factor3.849 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

रूप में उच्च रूप से नई चुनौतियों का सामना करते हैं विकसित देशों की सब्सिडी वाली कृषि यह भारतीय कृषि बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति में सुधार करके सफल और लाभदायक फिर हरित क्रांति के विकास,और जैविक खेती को बढ़ावा देने, और अनाज से उच्च मूल्य वाले फसलों को फसल पद्धति का विविधीकरण में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आर्थिक विकास में इसलिए वर्तमान अध्ययन पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करता है भारतीय कृषि परिचयरू वैश्वीकरण घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया है वैश्वीकरण घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्त, और माल और सेवाओं। वैश्वीकरण एक छोटा सा दुनिया बना देता है गाँव। वैश्वीकरण का अर्थ स्थानीय स्तर से दुनिया भर के स्तर पर बाजार का एक स्पष्टीकरण है। अभी वबाजार के लिए एक विशिष्ट स्थान की अवधारणा गायब हो रही है और पूरी दुनिया एक बन रही है बाजार वैश्वीकरण की प्रक्रिया आर्थिक विकास से संबंधित है। प्रतियोगिता है हर क्षेत्र में बड़े होकर वैश्वीकरण के पीछे का लक्ष्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जिससे कि कई परिवर्तन हो सकते हैं हर जगह बना दिया कृषि कई लोगों की आय का मतलब है भारत की 60: आबादी कृषि पर निर्भर करता है भारत का सकल घरेलू उत्पाद का 27: कृषि से मिलता है। श्रम शक्ति का 65:, और कुल निर्यात का 21: आबादी के बारे में दुनिया में भारत दूसरा स्थान है। दुनिया का 17. 5: जनसंख्या भारत में रहती है भारत कृषि उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, चावल, गेहूं, चीनी, सब्जियांय फल, काजू आदि का आयात करते हैं और दूध उत्पाद, काजू, फल, खाद्य आदि का आयात करते हैं तेल, चिकन, बीज आदि। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए सरकार के लिए नई नीति बनाता है कृषि क्षेत्र कृषि भारत में जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 60 प्रतिशत से अधिक भारत में लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में शामिल होते हैं। कृषि में सुधार के लिए क्षेत्रों, सरकार कृषि के लिए नई नीति बनाता है सरकार। कृषि पर कुछ सब्सिडी देता है उत्पादों जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक कृषिरू एक देश के आर्थिक विकास सीधे कृषि के विकास से संबंधित है। कृषि क्षेत्र लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं . भारत भी है आजादी के बाद से देश के कृषि को विकसित करने का प्रयास। कृषि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कम निवेश के लाभ और उद्योगों के आधार के साथ हमारी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जॉर्ज वॉशिंगटन के मुताबिक, ष्मुझे पता नहीं है कि इसमें कौन सी वास्तविक और महत्वपूर्ण भूमिका है सेवाओं को किसी भी देश में अपनी कृषि, इसकी उपयोगी नस्लों में सुधार के बजाय प्रदान किया जा सकता है जानवरों, और पंचायतों

की परवाह की अन्य शाखाएं। कृषि का विकास किया जा रहा है सरकार द्वारा दिया गया महत्व निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए

1. खाद्य सुरक्षा जारी करने के लिए
2. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के लिए कृषि समाज बनाने के लिए
3. किसानों के विकास को उत्तेजित करने के लिए
4. जीडीपी में वृद्धि कार्यप्रणाली और डेटा स्रोतरू

2. अध्ययन स्रोत

अध्ययन माध्यमिक डेटा पर आधारित है। डेटा को विभिन्न माध्यमिक से एकत्र किया गया था स्रोत जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण, सरकार भारत, किताबें, पत्रिकाओं, लेख, योजना और विभिन्न वेबसाइट।

भारतीय कृषि के वैश्वीकरण के प्रभाव

विशेषज्ञों का प्रिय है कि वैश्वीकरण कृषि क्षेत्र के संतुलित विकास में मदद करेगा, किसानों की आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन हो सकते हैं, कृषि उत्पाद होगा उचित मूल्य प्राप्त करें, रोजगार कृषि, ग्रामीण उद्योगों, कुटीर में उपलब्ध होंगे उद्योग, छोटे उद्योग शुरू होंगे और किसान खुश होंगे लेकिन यह विश्वास हो सकता है असत्य। विश्व व्यापार संगठन की नीति के मुताबिक कृषि को 50ः से आयात शुल्क कम करना है माल तक 2008. भारत को भविष्य में कृषि के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इसके अलावा, भारत को भी करना होगा घरेलू बाजार का 5ः आयात करें भारतीय आबादी में 25ः लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे हैं और 60ः आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इंग्लैंड में यह अनुपात 2ः, अमेरिका में 3ः और जापान में क्रमशः 7ः। भारत में सकल राष्ट्रीय आय में कृषि आय का हिस्सा 23.6ः, ऑस्ट्रेलिया में 5ः, कनाडा में 4ः, अमेरिका 3ः और इंग्लैंड 2ः क्रमशः। भारत में 62ः कुल कृषि भूमि का बारिश के पानी पर निर्भर करता है तकनीकी विकास नहीं कर सकते क्योंकि भूमि के पास क्षेत्र बहुत कम है। तो उत्पादन लागत अधिक है का उपयोग भारत में रासायनिक उर्वरक बहुत कम है यह भारत में केवल 84 किलो प्रति हेक्टेयर है लेकिन यह प्रति 266 किलो प्रति है चीन में हेक्टर, जापान में 360 किलोग्राम, बेल्जियम में 51 9 किलोग्राम। भारत में प्रदान किए गए ऋण की राशि कृषि भी बहुत कम है कृषि के लिए ऋण 15ः से 16ः की दर से प्रदान किया जाता है 7ः से 8ः की दर से वाहनों या मकानों के लिए प्रदान किए गए ऋण के साथ तुलना करें। का क्षेत्रफल भारत में पानी की जमीन 38ः है चीन में 52ः, जापान 62ः और पाकिस्तान में 72ः है। भारत में कृषि उत्पाद बहुत कम है भारत फलियां के उत्पादन में पहला है, दूसरा जड़ी बूटियों के उत्पादन में चावल और गेहूं और तंबाकू के उत्पादन में तीसरा। भारत चाय, कॉफी, चावल,

गेहूं, चीनी, तंबाकू, मसाला, काजू, तिल, तेल, फल और सब्जियां, मांस और मछलियों के साथ ही आयात फलियां, दूध उत्पाद, काजू फलों, खाद्य तेल, चिकन, बीज आदि। देश में खाद्य तेल का 50–60 लाख टन का आयात होता है और लगभग 15 हजार कोर रुपये खर्च होता है यह। भारत में कुल उत्पादित कृषि वस्तुओं में से 2: माल संसाधित होते हैं। मलेशिया में 80:, अमेरिका और ब्राजील 80: फिलीपीन 78: और ब्रितान में 70: माल संसाधित होते हैं। भारत में कुल कृषि उत्पाद में केवल ओ .32: व्यय कृषि अनुसंधान पर किया जाता है। में देशों में शोध पर व्यय की राशि 0.60: है और विकसित देशों में यह है 7:। भारत के लिए अपनी जगह वैश्विक प्रतिस्पर्धा रखना मुश्किल है क्योंकि भारतीय सामान कम हैं गुणवत्ता और मानक, यह कीमतों में उच्च है और माल की आपूर्ति अपर्याप्त और अस्थिर है लेकीन मे कृषि के क्षेत्र में देशों को आर्थिक सहायता, कोटा और बौद्धिक अधिकार के साथ आपूर्ति की जाती है धन बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के ग्रामीण इलाकों पर हमला कर रही हैं। कुछ राज्यों में देश हैं मुक्ति के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दिया ये कंपनियां उत्पादन करती हैं नकद फसलों और भविष्य में भोजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। विकसित देशों का उपयोग कर रहे हैं वैश्विक बाजार में अपनी श्रेष्ठता रखने के लिए डंपिंग तकनीक विकसित देशों को बेच रहे हैं प्रतियोगी की तुलना में कम कीमत पर अपने कृषि उत्पाद और इसके कुल उत्पादन से कम लागत। यह विकासशील देशों पर दुष्प्रभाव पैदा कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि विकसित देशों को 5: और विकासशील देशों को देना चाहिए अपने कृषि वस्तुओं के कुल मूल्य के 10: अनुदान दें लेकिन विकसित देशों की तरह अमेरिका, यूरोपीय देशों, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा को विभिन्न अनुदान दिए गए हैं कृषि क्षेत्र। विकासशील देशों पर उनके कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध है जैसे कि आयात शुल्क और कोटा विकसित देशों द्वारा दिए गए अनुदानों पर कोई सीमा नहीं है हरे रंग की बॉक्स और नीले बॉक्स के माध्यम से किसान तो, बहुत कम कीमतों पर विकसित देशों यह कृषि क्षेत्र और विकासशील देशों के किसानों के प्रभाव दूध, गेहूं, और मक्का अंतरराष्ट्रीय बाजार में नीचे आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका जैसे देशों और यूरोपीय देशों किसानों को किफायती सहायता प्रदान कर रहे हैं 2000–2001 में भारतीय सरकार ने 40 झीलों के गेहूं का निर्यात करने की अनुमति दी लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें भारतीय गेहूं बहुत अधिक हैं इसलिए भारत केवल 3 झीलों के गेहूं का निर्यात कर सकता है। के अध्यक्ष विश्व बैंक ने एक बार कहा था कि षविकसित देशों अनुदान के रूप में 280 से 300 अरब डॉलर देते हैं जब भारत अनुदान के रूप में 45780 कोर देता है। भारत में कृषि के मूल्य का अनुदान 4: से कम है माल। लेकिन डब्ल्यूटीओ अनुदान को

कम करने के लिए कहता है, क्योंकि विकसित देशों को अनुदान के बारे में नहीं बताया गया है। ऐसी परिस्थितियों में यह कहने के लिए एक अतिस्तृत नहीं होगा कि षविश्व व्यापार संगठनष है षविकसित देश व्यापार संगठनष के रूप में नामित होने के लिए भारत को सुरक्षा का उपयोग करने का अधिकार है खोल और अधिक आयात शुल्क चार्ज करने के लिए। विश्व व्यापार संगठन के 39 सदस्य देशों ने इसका इस्तेमाल किया भारत ने ऐसा नहीं किया सुरक्षा शेल का उपयोग करें यदि भारत सुरक्षा शेल का उपयोग करता है तो उसे कुछ लाभ मिलेगा और यदि विकसित देशों और विश्व व्यापार संगठन की वस्तुओं के अनुदान पर प्रतिबंध ठीक से किया जाता है, प्रतिस्पर्धी बाजार में भारत स्थिर होगा कृषि में विकास दररू कृषि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि जो प्रतिशत 4.7 था 8 के दौरान सालाना वें योजना (1 999–9 7) के दौरान उत्तरोत्तर 2.1 प्रतिशत की गिरावट आई 7वें योजना (1 99 7 – 02) और 1.8 प्रतिशत सालाना 10 के दौरानवें योजना (2002 – 07) और 3.6 प्रतिशत 11 वर्षों के दौरान वें योजना। नीचे की मेज में दिखाएं कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि ग्यारहवीं योजना लक्ष्य से कम हो गई है। लक्ष्य के मुकाबले कृषि और संबद्ध क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि 3.6 प्रतिशत पर है ग्यारहवीं योजना में 4.0 प्रतिशत क्षेत्र की कवरेज में स्पष्ट सीमा को देखते हुए, दीर्घकालिक विकास मुख्य रूप से क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी प्रसार को निर्भर करता है। यह प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक कृषि में सकल पूंजी तैयार करने का स्तर है सकल पूंजी निर्माण का अनुपात (निरंतर 2004–05 की कीमतों पर) कृषि क्षेत्र में जोड़ा गया मूल्य 2011 में बढ़कर 1 9 .8 प्रतिशत हो गया।

2007–08 में 16.1 प्रतिशत के स्तर से 12। हालांकि, कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा अर्थव्यवस्था की सकल पूंजी निर्माण में सकल पूंजी निर्माण ने मिश्रित प्रदर्शन किया है प्रवृत्ति। सरकार ने कृषि क्षेत्र को ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया है। में हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में वास्तविक ऋण इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। 2012–13 में, 575000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले, कृषि को वास्तविक ऋणृ 239629 करोड़ में रखा गया था सितंबर 2012 के अनुसार। फसलों में पैदावार पर। इसके माध्यम से प्राप्त करने की मांग की गई है वृद्धिशील उत्पादकता

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 4, Issue 11 , November 2014 Impact Factor3.849 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

तालिका एक

कृषि और समग्र सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक औसत वृद्धि दर (प्रतिशत में)

पंचवर्षीय योजना	समग्र सकल घरेलू उत्पाद विकासजीडीपी में वृद्धि की दर मूल्यांकन करें	कृषि और संबद्ध क्षेत्रों
7 वीं योजना 1 985 - 1 99 0	6.0	3.2
वार्षिक योजना 1 99 0 - 1992	3.4	1.3
8 वीं योजना 1992 - 1 99 7	6.7	4.7
8 वीं योजना 1992 - 1 99 7	5.5	2.1
10 वीं योजना 2002 - 2007	7.6	2.3
2002 - 2003	3.8	7.2
2003 - 2004	8.5	10.0
2004 - 2005	7.5	0.00
2005 - 2006	9.0	6.00
2006 - 2007	9.2	2.7
2010 - 2011	NA	7.9
2011 - 2012	NA	3.6

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार, 2007-2008 और 2012-2013
(NA = उपलब्ध नहीं है)

भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव निम्नानुसार हैं –

1. राष्ट्रीय आय – के कृषि वस्तुओं के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार प्राप्त करना भारत, कृषि उत्पाद, नई तकनीक, नए बीज आदि में वृद्धि हुई है। कृषि उत्पाद को बढ़ाने में मदद की
2. रोजगार में वृद्धि – कृषि उत्पादों के निर्यात हालांकि यह वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक है उत्पादों, इसकी मानकीकरण और प्रसंस्करण, पैकिंग आदि। उद्योगों के आधार पर कृषि संग्रहीत हैं और इसे रोजगार में वृद्धि पर बनाया गया है।
3. अनुदान कम करने के लिए कोई जरूरत नहीं – के लिए कृषि समझौते सीमा की स्थिति के अनुसार अनुदान विकासशील देशों के लिए उत्पादन मूल्य का 10: तय किया गया है। लेकिन आर्थिक रूप से अनुदान हमें 10: से कम प्राप्त हुआ है इसलिए कमी की कोई आवश्यकता नहीं

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 4, Issue 11 , November 2014 Impact Factor3.849 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

है। क्योंकि विश्व व्यापार संगठन की शर्तों देशों के सभी पाने के लिए

4. व्यापार में हिस्सेदारी में वृद्धि एक ही अवसर है इसलिए कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है।
5. कृषि वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है – कृषि वस्तुओं की कीमतों में अधिक है भारतीय बाजारों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार यदि विकसित देशों ने अनुदान घटा दिया, तो वे कीमतों में वृद्धि हुई है इसलिए भारतीय बाजार में निर्यात में वृद्धि होगी और अगर कीमतों में वृद्धि, वहाँ लाभ होगा

भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं –

1. विकसित देशों द्वारा बड़े पैमाने पर वितरित अनुदान – में कमी करने से पहले विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुदान, विकसित देशों ने बड़े पैमाने पर अनुदान वितरित किया था वे बढ़ रहे थे 1988–1994 के दौरान कृषि के बड़े पैमाने पर अनुदान की राशि इसलिए उन्हें सामना नहीं करना है कई कठिनाइयों अगर अनुदान में कमी है
2. छोटे उत्पादन क्षेत्र – भारत में जनसंख्या के 60: कृषि पर निर्भर हैं। पर दबाव बढ़ती आबादी के कारण कृषि बढ़ रही है। भूमि का कब्जा छोटा है और ऐसा है उत्पादन लागत अधिक है मानक आदि की समस्या भी है। इसलिए प्रतिकूल हैं भारतीय कृषि पर प्रभाव पड़ता है
3. बौद्धिक संपदा अधिकाररू – बौद्धिक संपदा अधिकार भारतीय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है कारण कृषि। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कृषि के क्षेत्र में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं और यह खराब होगी मार्जिन किसानों के लिए
4. उत्पादन खर्च और माल की कम लागत को बढ़ाना – किसानों दिवालिया किया जा रहा है बढ़ते उत्पादन व्यय, महंगा बीज, एक तरफ और कीमतों को कम करने के कारण दूसरी तरफ माल वह इससे बाहर नहीं निकलता और इसलिए वह आत्महत्या कर रहा है। यह एक हो सकता है

3. सुझाव

1. बुनियादी सेवाओं में वृद्धि करने के लिए यह मानक और बुनियादी के दायरे को विकसित करने के लिए आवश्यक है घरेलू सड़कों, बंदरगाहों, आधुनिक संचार, भंडार, मानक जैसे सेवाओं नियंत्रण आदि। ये सुविधाएं निर्यात के लिए प्रेरणा पर होंगे।

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 4, Issue 11 , November 2014 Impact Factor3.849 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

2. वित्त और विद्युत आपूर्ति – भारतीय कृषि के लिए बिजली की आपूर्ति अनियमित है और अपर्याप्त। कृषि के लिए वित्त की कमी भी है। यह के मानक पर प्रभाव उत्पादन और उत्पादन का व्यय इसलिए बचने के लिए उचित नीतियों को लागू करना आवश्यक है ये समस्याएं।
3. बढ़ाने से प्रोडक्शंस और निर्यात – एक आयात शुल्क के लागू लंबे समय के लिए उपयोगी नहीं है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करते समय क्योंकि अगर भारत आयात शुल्क बढ़ाता है, तो अन्य देशों ने अपने अनुदान में वृद्धि इसलिए हमें अपने उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करना होगा
4. उत्पादन की योजना – यह फसलों को बढ़ाने के लिए केवल क्योंकि हम अच्छे दाम मिल अच्छा नहीं है। लेकिन फसलों के बढ़ने की योजना आवश्यक है ताकि अच्छे उत्पादन की कीमतों में वृद्धि कम न हो ।

4. निष्कर्ष

भारत वैश्विक प्रवाह में शामिल है कृषि की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करना जरूरी है निर्यात में उत्पाद कृषि के क्षेत्र में समस्याओं का अध्ययन करना और बचाना महत्वपूर्ण है उन्हें। उदाहरण के लिए, बिजली की अनियमित और अपर्याप्त आपूर्ति, बुनियादी सेवाओं की कमी, उत्पादन में कमी, बढ़ती फसलों की योजना की कमी, वित्त की कमी, बारिश पर निर्भरता आदि उत्पादों को उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। प्रसंस्करण उद्योगों को कृषि वस्तुओं पर संसाधित करने के लिए विकसित किया गया है। किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और कृषि संबंधित उद्योग शुरू करने के लिए मार्गदर्शन अगर ये उपचार भारतीय बनाये जाते हैं वैश्वीकरण में कृषि को उत्साहित कर सकते हैं

सन्दर्भ

1. क्तै.वउेंमींत, कश्मीर, ष्भारतीय कृषि एवं चुनौतियां पर वैश्वीकरण का प्रभाव –। एक गंभीर समीक्षा।, कला वाणिज्य और साहित्य के इंटरनेशनल जर्नल, वॉल्यूम 1 अंक 20 फरवरी 2013, आईएसएसएन 2320–4370।
2. चंदन सेन गुप्ता, ष्भूमंडलीकरण ब्वदबमचजनंसप्रपदहष्, आर्थिक और च्वसपजपबंसॅममासल, 18 अगस्त, 2001।
3. ठाकुर, एस, ष्भूमंडलीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्थाष्, तीसरा अवधारणा, जून, 1997।

4. वर्मा, जग मोहन सिंह, ष्वैश्वीकरण और भारत में आर्थिक सुधारष्, तीसरा अवधारणा, अप्रैल, 2001।
5. नरसिम्हा राव और ।दरंपी, एड में श्भारत ।हतपबनजसनतम पर वैश्वीकरण का प्रभाव ष्। वॉल्यूम। ग्रामीण भारत में विकास एक बहु–विषयक विश्लेषण, धारावाहिक प्रकाशन, नई दिल्ली .2005
6. यादव, एस एस (2001), षविश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि पर इसका प्रभावष्, योजना, वॉल्यूम। 45।
7. कौशिक, संजय।, ठींतकूंर सुनील और राजीव गोयल, ष्वैश्वीकरण और भारतीय कृषि पर इसका प्रभाव भारत में, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज, वॉल्यूम 2, नंबर 1, जनवरी 2013, आईएसएसएनरू 2278–6236
8. आर्थिक सर्वेक्षण 2012–13